महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार पत्र

RNI No. MAHHIN/2013/49425
डाक पंजीयन सं. MNW/251/2016-2018
e-paper : www.srushtiagronews.com

Posted at Malad NDPO Dated of Posting
4th to 5th for (1st to 15th issue)
18th to 19th for (16th to 30th issue)

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

सृष्टि एग्रो

वर्ष-6 | अंक-10 | मुंबई, 16 से 30 जून 2018 | मूल्य - 2 रुपए | पृष्ठ - 8

सिकुड़ेगा कपास का रकबा!

सुरेश शर्मा

मुंबई (कासं)। कपास के रकबे में इस साल 10-12 प्रतिशत की कमी आने की आशंका है, क्योंकि किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सोयाबीन और धान जैसी अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। कपास के तहत रकबा इस साल घटकर 107 लाख हेक्टेयर रह जाने का अनुमान है, जो पिछले साल 122 लाख हेक्टेयर था। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस फसल में कम दिलचस्पी दिखाई गई है। कपास के प्रति किसानों की घटती दिलचस्पी के लिए दो प्रमुख कारकों को जिम्मेदार माना जा सकता है। पहला, कपास फसल पिछले साल पिंक बॉलवॉर्म नाम के कीड़े से प्रभावित हुई थी जिससे किसानों में इस साल भी इसे लेकर आशंका बनी हुई है। यही वजह है कि वे अन्य वैकल्पिक फसलों पर ध्यान दे रहे हैं। भारत में कपास व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्था कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआईए) के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा, 'हमें इस साल कपास के रकबे में 10-12 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है।' किसानों को सिंचाई की किल्लत, प्रतिकूल मौसम

और पिंक बॉलवॉर्म के डर जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे इस खरीफ सत्र में कपास की बुआई पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है। किसान कपास के बदले गुजरात में मूंगफली, हरियाणा में धान और महाराष्ट्र तथा तेलंगाना क्षेत्र में सोयाबीन की ओर रुख कर सकते हैं क्योंकि कपास कीमतें अन्य उपलब्ध विकल्पों की तुलना में ज्यादा फायदेमंद नहीं रह गई हैं। इसी तरह, सोयाबीन, दालें और गन्ने का रकबा भी कपास से ज्यादा देखा जा सकता है क्योंकि कीमतें मजबूत रही हैं और कीटनाशकों का प्रभाव इन फसलों पर कम पड़ता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) पर कपास कीमतें 21,700 रुपये प्रति गांठ (एक गांठ= 170 किलोग्राम) पर कारोबार कर रही हैं, जो सालाना आधार पर 3.23 प्रतिशत तक ज्यादा है। इस साल के लिए कीमत परिदृश्य मजबूत बना हुआ है और हम कीमतों में 8-10 फीसदी की और तेजी देख सकते हैं क्योंकि भारत में कम कपास रकबे की उम्मीद से कीमतों को मजबूती मिल सकती है। कपास के रकबे में कमी से भारत के कपास उत्पादन आंकड़े में गिरावट दर्ज की जा सकती है। टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन कॉटन एडवाइजरी बोर्ड (सीएबी) द्वारा पहले अग्रिम अनुमान में भारत का कपास उत्पादन 3.77 करोड़ गांठ रहने का अनुमान जताया गया था।

महाराष्ट्र में किसानों ने किया रिकॉर्ड तोड़ दाल का उत्पादन

मुंबई (कासं)। सरकार ने दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों से अपील की थी, जिसके बाद किसानों ने सरकार की बात मानते हुए दाल का बंपर उत्पादन किया, लेकिन अब महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, लातूर और वर्धा समेत कई जिलों में किसान अपनी दाल बेचने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। विदित हो कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि मेरी एक प्रार्थना को, मेरी एक विनती को मेरे देश को किसानों ने जिस प्रकार से सर आंखों पर बिठा कर के मेहनत की और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन किया, इसके लिए मेरे किसान भाई-बहन विशेष धन्यवाद के अधिकारी हैं। किसानों ने दाल उत्पादन के इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन जमीन पर उन्हें क्या मिला? जिन किसानों ने इतनी मेहनत से दाल का उत्पादन किया उनकी दाल इस

सरकारी बिक्री केंद्र पर नहीं बिक पा रही है। न तो गोदाम में दाल रखने की जगह बची है और न ही बोरियां, जिनमें ये दाल सुरक्षित रखी जा सके। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस साल रिकॉर्ड 50 लाख क्विंटल अरहर दाल का उत्पादन हुआ है। किसानों की मानें तो आज गोदामों मे 99 प्रतिशत व्यापारियों का माल है और किसानों का माल सिर्फ एक प्रतिशत है। किसानों की ये समस्या किसी एक मंडी की नहीं है। देश की अरहर दाल की सबसे बड़ी मंडी लातूर का भी यही हाल है। मराठवाड़ा के लातूर की मंडी इन दिनों दिन-रात किसानों के शोर-शराबे में डूबी हुई है। किसानों का आरोप है कि खाद्य संग्रहण, वितरण और भंडारण का काम देखने वाली सरकारी एजेंसी नाफेड के केंद्र पर किसानों की बजाय व्यापारियों की दाल खरीदी जा रही है। यही हालात वर्धा समेत राज्य के कई जिलों में हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बढ़ेगी ऋण की सीमा

मुंबई (कासं)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध बैंक ऋण की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक की दूसरी मौद्रिक नीति समिति की चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक बैठक के बाद विकास एवं नियामक नीतियों पर जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मकान के निर्माण के लिए अब बैंक शहरी इलाकों (10 लाख या ज्यादा की आबादी वाले शहरों) में 35 लाख रुपए और ग्रामीण इलाकों में 25 लाख रुपए तक का आवास ऋण दे सकेंगे। योजना के तहत ये ऋण प्राथमिकता वाले सेक्टर की श्रेणी में दिए जाते हैं। पहले यह सीमा क्रमशः 28 लाख रुपए और 20 लाख रुपए थी। इसके लिए शर्त यह है कि मकान की कुल लागत शहरी क्षेत्रों में 45 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख रुपये से ज्यादा न हो। इसके लिए 30 जून तक सर्कुलर जारी करने की बात कही गई है। आरबीआई ने कहा है कि आवास ऋण के आंकड़ों के विश्लेषण में यह भी पाया है कि दो लाख रुपए तक के आवास ऋण में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति का प्रतिशत काफी ज्यादा है और यह तेजी से बढ़ रहा है। बैंकों को इस राशि तक के आवास ऋण जारी करते समय ग्राहकों की पात्रता आदि की जांच में काफी ध्यान देने की जरूरत है।

अरहर की नई किस्म आईपीए-203 विकसित

मुंबई (कासं)। जून महीने में बारिश के बाद अरहर की बुवाई शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार सही बीज न बोने से कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। ऐसे में किसान अरहर की उन्नत किस्मों को अपनाकर अरहर की फसल को बीमारियों से बचा सकता है। केन्द्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सात वर्षों के शोध के बाद दाल की नई किस्म आईपीए-203 विकसित की है, जिसमें अरहर में होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एनपी सिंह बताते हैं, जून में अरहर की बुवाई शुरू हो जाती है, अभी तक जो किस्में हैं उनमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। पहली बीमारी उकठा होती है, जिसमें पौधे सूखने लगते हैं, दूसरी बीमारी में पौधों पर पत्तियां तो लगती हैं, लेकिन फूल और फल नहीं लगते हैं। अरहर में होने वाले रोगों से किसानों को हर वर्ष हजारों टन अरहर की फसल का नुकसान होता था। नई प्रजाति इन दोनों बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त है। आमतौर पर प्रति हेक्टेयर अरहर उत्पादन नौ से दस कुंतल होता है, लेकिन अरहर

की यह नई प्रजाति आईपीए 203 बोने से किसानों को प्रति हेक्टेयर करीब 18 से 20 कुंतल तक उत्पादन होता है। जल्दी पकने वाली प्रजातियों की बुवाई जून के पहले हफ्ते में बुवाई करनी चाहिए साथ ही देर में पकने वाली अरहर की प्रजातियों को जुलाई में बोना चाहिए। इस किस्म के अलावा किसान दूसरी उन्नतशील प्रजातियां भी प्रयोग कर सकता है। पहली अगेती प्रजातियां होती हैं, जिसमे उन्नत प्रजातियां पारस, टाइप-21, पूसा-992, उपास-120, दूसरी पछेती या देर से पकने वाली प्रजातियां पूसा-9, नरेन्द्र अरहर-1, आजाद अरहर-1, मालवीय विकास, मालवीय चमत्कार जिनको देर से पकने वाली प्रजातियां हैं।

किसानों को सताने लगी पिंक बॉलवार्म की चिंता

मुंबई (कासं)। पिंक बॉलवार्म की वजह से सारे किसान चिंता से ग्रस्त है। पिंक बॉलवार्म एक ऐसा कीड़ा है जो कपास की फ़सल को बर्बाद करता है। महाराष्ट्र में किसानो और ट्रेडर्स को चिंता सता रही है कपास की फसल की। क्योंकि इंटरनेशनल और घरेलु व्यापार में कपास की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ऐसे में पिंक बॉलवार्म नामक कीड़े की वजह से कपास के उत्पादन में कोई कमी न आये।

पिंक बॉलवार्म से बचने के तरीके: कपास की फसल को खत्म कर दो महीने तक खेत को खाली रखने की सलाह दी क्योंकि यह कीड़ा केवल कपास में ही जीवित रह सकता है , खाली खेतों में यह कीड़ा मर जाता है। गुजरात सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए पिंक बॉलवार्म को खत्म किया है। अप्रैल और मई इन दो महीने ज्यादा फसल रखने से किसानो को लगभग दस हज़ार रुपए ज्यादा आय होती है ऐसे में किसानो को फसल हटाने के लिए मानना मुश्किल हो जाता है। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि जीएसटी और नोटबंदी के कारण कपास की मांग कम हुई थी लेकिन अब एक बार फिर से कपास की डिमांड बढ़ने लगी है।

सम्पादकीय

गन्ना किसानों की समस्याएं

उत्तर प्रदेश के गन्ना क्षेत्र कैराना में हार के एक सप्ताह बाद केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने चीनी उद्योग व किसानों के बकाया भुगतान के लिए 8,500 करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज की घोषणा की है। अभी यह कहना मुश्किल है कि यह पैकेज चीनी उद्योग व किसानों के लिए कितना हितकारी साबित होगा, फिर भी यह पहल एक प्रकार से अच्छी है। वर्तमान में चीनी उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। भारी उत्पादन व ज्यादा स्टाक से चीनी के दाम बाजार में काफी गिर गए हैं। इससे मिलों की लागत नहीं निकल पा रही है। भारत में चीनी खपत 2.50 करोड़ टन के लगभग है, जबकि उत्पादन 3.15 करोड़ टन से ज्यादा हो गया है। मिलों के लिए गन्ना किसानों का करीब 22 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करना कठिन हो गया है। भुगतान न होने की वजह से किसान सरकार से नाराज हैं। इसलिए सरकार ने राहत पैकेज घोषित करने की जरूरत समझी। अब प्रयास रहेंगे कि चीनी के मूल्य लागत निकालने के लिए तय किए जाएं और किसानों के भुगतान की भी राह खुल सके। बेशक, इससे चीनी के खुदरा मूल्य बढ़ेंगे, लेकिन चीनी मिलों की लागत निकलेगी। राहत के दूसरे कदम के तहत चीनी के आयात शुल्क को सौ प्रतिशत कर दिया गया है ताकि कोई आयात न कर सके क्योंकि आयातित चीनी महंगी होगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए 20 लाख टन तक के चीनी को निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। इसके लिए 30 लाख टन का बम्फर स्टाक रहेगा जिस पर 1175 करोड़ रुपए का भार आएगा। चीनी मिलें चीनी के साथ-साथ इथनॉल उत्पादन भी करें, इसके लिए पांच साल तक की रियायती कर्ज का फैसला लिया गया है। इसके लिए 4,440 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसमें ब्याज रियायत है, जिससे सरकार को 1332 करोड़ रुपए भार सहन करना होगा। यह चीनी उद्योग के लिए एक व्यावहारिक फैसला है। यह जाहिर है कि गन्ने से केवल चीनी पैदा की जाएगी तो मिलों को घाटा होगा और किसानों को गन्ने का तय मूल्य मिलना मुश्किल हो जाएगा। साफ है कि इथनॉल उत्पादन करेंगे तो मिलों को घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा और देश में पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इससे सरकार को लाभ होगा। यह सब ठीक है, लेकिन बड़ी चुनौती किसानों के बकाया के भुगतान की फिर भी रहेगी। उनके भुगतान के लिए सिर्फ एक हजार पांच सौ करोड रुपए रखे गए हैं।

गन्ना किसानों के लिए फौरी राहत मात्र होगी। चीनी मिलों पर किसानों का बकाया कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि कई सालों से किसान भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। फिर वे आंदोलन करने को मजबूर होते हैं और कई बार आत्महत्या जैसे कदम तक उठा लेते हैं। चिंताजनक बात यह है कि सरकारें चीनी उद्योगों को तो राहत देती रहती है, लेकिन किसानों के हितों पर अपेक्षित गौर नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों की बकाया रकम बारह हजार करोड़ के लगभग है। सवाल है कि इतनी बड़ी रकम मिलें कैसे और कब चुकाने की स्थिति में होगी। यह बकाया राशि सालों से बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या ही बकाया राशि की वसूली रही है। किसान चीनी मिलों को गन्ना बेचते हैं तो उसके तत्काल भुगतान की व्यवस्था हो तो, यह किसानों के लिए राहतकारी ही होगी। अतः राहत पैकेज अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें किसानों को ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। बकाया भुगतान और गन्ने की खरीद का तत्काल भुगतान की व्यवस्था किसानों को राहत दिला सकती है और उन्हें खुशहाल भी बना सकती है।

राज्य शुल्कों का रिफंड होगा जारी

मुंबई (कासं)। भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सरकार जल्द ही राज्य शुल्कों के रिफंड (आरओएसएल) के तहत कुल बकाया राशि का 60 प्रतिशत जारी करने की तैयारी में है। इससे कपड़ा और वस्त्र निर्माताओं को कार्यशील पूंजी की तंगी से राहत मिल सकती है। हाल ही में हुई एक बैठक में सरकार ने पिछले साल वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से रोके गए राज्य शुल्कों के रिफंड की 60 प्रतिशत बकाया राशि को मंजूरी देने के लिए जल्द ही 15 अरब रुपये जारी करने का आश्वासन दिया है। एक अनुमान के मुताबिक, राज्य शुल्कों की वापसी के तहत सरकार के पास 25 अरब रुपये की राशि अटकी हुई है। इसने परिधान और तैयार वस्त्र समेत पूरे कपड़ा उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध कर दिया है।

सरकार के पास इतनी बड़ी रकम अवरुद्ध पड़ी होने के बावजूद, भारतीय वस्त्र निर्यातक अपने ऋणदाताओं को ब्याज का भुगतान कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उद्योग को दोगुना झटका झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार, राज्य शुल्कों की रिफंड राशि जारी किए जाने से इस तिमाही केबाद कपड़ा निर्यातकों की सकल आय और शुद्ध आय बेहतर होगी, क्योंकि सरकार ने पर्याप्त कोष उपलब्ध कराने के बाद कपड़ा क्षेत्र के भागीदारों को खेप की तारीख से दो सप्ताह में राज्य शुल्कों के रिफंड की राशि जारी करने का आश्वासन दिया है। सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) के चेयरमैन उज्जवल लाहोटी ने कहा कि यह कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी राहत है।

एक ओर जहां निर्यातक राज्य शुल्क रिफंड के तहत इतनी बड़ी राशि अटकने के कारण कार्यशील पूंजी की तंगी का सामना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर निर्यातक सरकार के पास अवरुद्ध पड़े धन पर उधारदाताओं को ब्याज का भुगतान कर रहे थे।

इस आश्वासन सेवस्त्र निर्यातकों को इस दोहरी मार से राहत मिलेगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ हुई इस बैठक में यह फैसला किया गया कि राज्य शुल्कों के रिफंड का शेष 40 प्रतिशत जल्द ही जारी किया जाएगा।

कपास की फसल में रस चूसने वाले कीड़े एवं उनका प्रबंधन

कपास एक प्रमुख नकदी फसल है। यह खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। हरियाणा में कपास की औसत पैदावार 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ है परन्तु कई प्रगतिशील किसान उन्नत कृषि क्रियाएं अपनाकर 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार लेने में सफल हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से कपास की उत्पादकता घटी है, जिसमें कीटों की अहम भूमिका रही है। कीटों के प्रकोप के कारण पैदावार में 60-70 प्रतिशत तक कमी आ जाती है तथा इसके साथ ही उपज की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कपास को हानि पहुँचाने वाले कीटों में रस चूसने वालें कीट भी शामिल हैं। इन कीटों में सफेद मक्खी, हरा तेला, चेपा, मीली बग प्रमुख हैं जिनके प्रकोप के कारण 20-30 प्रतिशत पैदावार कम हो जाती है। इन कीटों का विवरण एवं प्रबंधन इस प्रकार है-

सफेद मक्खी: पिछले कुछ वर्षों से कपास में सफेद मक्खी का प्रकोप काफी बढ़ रहा है। यह एक बहुभक्षी कीट है जो कपास की प्रारंभिक अवस्था से लेकर चुनाई व कटाई तक फसल में रहता है। कपास के अलावा खरीफ मौसम में यह 100 से भी अधिक पौधों पर आक्रमण करती है। इस कीट के शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसते हैं। प्रौढ़ 1-1.5 मि.मी. लम्बे, सफेद पंखों व पीले शरीर वाले होते हैं। जबकि शिशु हल्के पीले, चपटे होते हैं। ये फसल को दो तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। एक तो रस चूसने की वजह से, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। दूसरा पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ने की वजह से, जिस पर काली फफूंद उग जाती है। जो कि पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया में बाधा ड़ालती है। यह कीट कपास में मरोड़िया रोग फैलाने में भी सहायक है। इसका प्रकोप अगस्त-सितम्बर मास में ज्यादा होता है। जिनसे पौधे की बढ़वार रुक जाती है।

चेपा/अल: चेपा के शिशु और प्रौढ़ दोनो पत्तियों की निचली सतह व कोपलों से लगातार रस चूसते रहते हैं। जिसके कारण पत्ते मुड़ने लगते हैं। ये कीट छोटे आकार के गोल, हल्के पीले रंग के होते हैं और एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ते हैं जिससे पौधों पर काली फफूंद उग जाती है। ग्रसित पत्ते तेल में डुबोए हुए से लगते हैं। इस कीट का प्रकोप सितम्बर से अक्टूबर माह में बढ़ जाता है। इस कीट के आक्रमण के कारण पौधा कमजोर हो जाता है, पत्ते मुड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं।

हरा तेला: इन कीटों के शिशु व प्रौढ़ दोनों ही कपास को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हरे रंग के होते हैं जो कि पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं और टेढ़े चलते दिखाई देते हैं। इनके आक्रमण से पत्ते किनारों से पीले पड़ जाते हैं तथा नीचे की ओर मुड़ने लगते हैं, बाद में कप नुमा हो जाते हैं। पत्तियां पीली व लाल होकर सूख जाती है और जमीन पर गिर जाती हैं। पौधों की बढ़वार रुक जाती है व कलियां, फूल गिरने लगते हैं। जिससे पैदावार कम हो जाती है। हरा तेला जुलाई से अगस्त माह में सर्वाधिक हानि पहुँचाता है।

चुरड़ा: ये कीट छोटे पतले शरीर वाले भूरे रंग के होते हैं जो पत्तों की निचली सतह पर नाड़ियों के साथ चलते दिखाई देते हैं। प्रौढ़ प्राय: गहरे भूरे रंग के होते हैं। शिशु तथा प्रौढ़ पत्तों की निचली सतह को खुरच कर रस चूसते हैं। चुरड़ा ग्रसित पत्तियों की निचली सतह को अगर धूप की ओर किया जाए तो वह चाँदी की तरह चमकती है। अगर लम्बे समय तक मौसम खुश्क रहे तो इस कीट का प्रकोप काफी बढ़ जाता है जिससे पत्ते सूख कर गिर जाते हैं।

मीली बग: यह एक बहुभक्षी कीड़ा है जो पौधों के विभिन्न भागों में समूह में एकत्र होकर रस चूसते है तथा पौधे के जिस भी भाग पर यह अपनी कालोनी बना लेते हैं, उसे सूखा देते हैं। यह कीट लगभग 3-4 मि.मि. लंबा व सफेद रंग का होता है। इसका शरीर पंख रहित होता है। इस कीट से प्रभावित पौधों के पत्ते व फल गिर जाते हैं। यह कीट एक प्रकार का मधुस्त्राव छोड़ता है। जिस पर काली फफूंद लग जाती है। मीली बग ग्रसित पोधों पर प्राय: काली/भूरी चींटियाँ काफी संख्या में चलती नजर आती है।

रस चूसक कीटों का एकीकृत प्रबंधन-

-अगेती व पछेती बिजाई में कीड़ों का प्रकोप अधिक रहता है। इसलिए कपास की बिजाई मध्य अप्रैल से मई तक कर लें।

-पिछली फसल की जड़ों एवं डंठलों को एकत्रित कर नष्ट करें।

-कपास के खेत के आसपास या मेड़ों पर उगे हुए खरपतवार को नष्ट कर दें, क्योंकि इन पर सफेद मक्खी व अन्य कीटों को आश्रय मिलता है।

-खाद का संतुलित प्रयोग करें। नत्रजन वाली खाद अधिक न ड़ालें।

-कीटनाशकों की कम या अधिक मात्रा नही डालें बल्कि सिफारिश की गई मात्रा ही डालें।

-सिंथेटिक पाइरेथ्राइड समूह वाले कीटनाशकों का उपयोग सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए ना करें।

-पीले पाश प्रयोग सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए करें।

-रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कीटों के आर्थिक कगार पर पहुंचने के बाद ही करें।

-मई के अंत, जून व जुलाई तक चुरड़ा, हरा तेला के लिए 250-350 मि.ली. ड़ाइमेथोएट (रोगेर) 30 ई.सी. या 300-400 मि.ली. आक्सीड़ीमेटान मिथाइल (मैटासिस्टाकस) 25 ई.सी. या 40 मि.ली. ईमीड़ाक्लोपरिड़ (कोन्फीड़ोर) 200 एस. एल. को 120-150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।

-यदि अगस्त सितम्बर माह में सफेद मक्खी का आक्रमण हो जाए तो, सफेद मक्खी के आर्थिक कगार पर पहुँचने पर 300 मि.ली. डाइमेथोएट 30 ई.सी. या मैटासिस्टाक्स 25 ई.सी. व एक लीटर नीम आधारित कीटनाशक का बारी बारी से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।

-मीली बग के लिए 3 मि ली. प्रोफेनोफास 50 ई.सी. या 5 ग्राम थायोड़िकार्ब 75 ड़ब्लयू. पी. या 4 मि.ली. क्विनलफास 25 ई.सी. प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

रूमी रावल एवं कृष्णा रोलानियाँ, कीट विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

बीजोपचार और बीज भंडारण अधिक उत्पादन की एक सफल तकनीक

राजवीर यादव ,डॉ. अनुराग आर.तायडे ,राजेश कुमार मीना,सैम हिग्गिंबोटोम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस अल्लाहाबाद (उ.प.)

फसलों में दो प्रकार के बीज जनित रोग पाए जाते है। ये हैं अंत: एक बाह्य जनित रोग। इसमें बीन एन्थ्रेक्नोज, बंधा गोभी का ब्लैक लेग, धान का जीवाणु पत्ती अंगमारी, कपास का जीवाणु अंगमारी, गेहूँ एवं जौ का अनावृत कंड तथा धान का आभारी कंड अंत: बीज जनित एवं अल्टरनेरिया (आलू एवं टमाटर का अगेती झुलसा, सरसों कुल का अंगमारी एवं प्याज में अंगमारी), यूजेरियम, हेल्मिन्थोस्पोरियम, सर्कोस्पोरा आदि बाह्य बीज जनित रोग कारक है। इनसे अनाज तथा सब्जी फसलों को काफी नुकसान होता है। अगर हम फसल सुरक्षा की बात करते है तो बीज उपचार द्वारा फसलों में होने वाले नुकसान को कम करके 15 से 20 प्रतिशत तक शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है।

फसल उत्पादन में बीज की भूमि अहम है। एक स्वस्थ एवं उन्नत बीज ही अच्छे फसल का मुख्य आधार है। अतएव किसान भाईयों, अनुशंसित किस्म जिसमें रोग/कीट रोधी क्षमता हो, का चयन करें। जहां तक रोग रोधी किस्मों के चयन का प्रश्न है तो प्रत्येक फसल में इस प्रदेश हेतु रोग रोधी किस्में उपलब्ध नहीं है। अगर है भी तो कई जगहों पर समान रूप से किसान भाईयों को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए या तो जानकारी का आभाव, बाजार में समय पर उन किस्मों का नहीं होना था पैसा का अभाव समझा जा सकता है। अब ऐसे में किसान भाई क्या करें? क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय/तकनीक है जिससे कि रोग/कीट रोधी किस्मों के न होने पर भी आप अपने फसल की अच्छी पैदावार ले सकें? हाँ किसान भाई, बीज उपचार है न आप के पास। बीज उपचार का मतलब है किस प्रकार, किस मात्र में फफूंद नाशी/कीटनाशी/जीवाणु नाशी रसायनों अथवा अन्य परजीवी नाशी कारकों आदि का इस्तेमाल कर बीज विगलन, झरण अथवा बीज जनित विकारों से छुटकारा पाना।

बीजोपचार की विधियाँ

बीजोपचार, बीज जनित रोगों की रोकथाम का सबसे सस्ता व सरल उपाय है, बीजोपचार का मुख्य उद्देश्य बीज तथा भूमि में उपस्थित रोग जनकों से बीज की रक्षा करना है।

बीजोपचार की निम्नलिखित विधियाँ है:-

भौतिक विधियाँ : बीजोपचार की भौतिक विधियाँ प्राचीनकाल से ही प्रचलित है, 1670 में गेहूँ से भरे जहाज में समुद्र का खारा पानी भर गया जब इस गेहूँ को पुन: सुखाकर बीज के रूप में बोया गया तब यह पाया गया कि उनसे उगे गेहूँ के पौधे बदबूदार कंडवा रोग से ग्रस्त नहीं हुए। ऐमनेंट ने सन 1637 में नमक को बीजोपचार रूप में प्रयोग कर गेहूँ के कंडवा रोग की रोकथाम की। इसी प्रकार प्राचीनकाल से ही यह प्रचलित है कि बोने से पूर्व बीज को सूर्य की तेज धूप में सुखाया जाये और फिर बोया जायें।

सूर्यताप द्वारा बीजोपचार : बीज के आंतरिक भाग में (भ्रूण) में रोगजनक को नष्ट करने के लिए रोगजनक की सुषुप्तावस्था को तोड़ना होता है, जिसके बाद रोगजनक बिल्कुल नाजुक अवस्था में आ जाता है, जिसे सूर्य की गर्मी द्वारा नष्ट किया जा सकता है। गेहूँ, जौ एव जई का छिद्रा कंडवा रोग आंतरिक बीज जन्य रोग है। इनके नियंत्रण हेतु बीज को पहले पानी में 3-4 घंटे भिगोते है और फिर सूर्य ताप में 4 घंटे तक रखते है, जिससे बीज के आंतरिक भाग में उपस्थित रोगजनक का कवकजाल नष्ट हो जाता है।

गर्म जल द्वारा बीजोपचार : इस विधि का प्रयोग अधिकतर जीवाणु एवं विषाणुओं की रोकथाम के लिए किया जाता है। इस विधि में बीज या बीज के रूप में प्रयोग होने वाले भागों को 53-54 डिग्री सेल्सियस तापमान किया 15 मिनट एक रखा जाता है जिससे रोगजनक नष्ट हो जाते हैं, जबकि बीज अंकुरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यदि गाजर के बीज को गर्म जल में 50 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाये तो आल्टरनेरिया नष्ट हो जाता है।

गर्म वायु द्वारा : गर्म वायु के प्रयोग द्वारा भी बीजों को उपचारित किया जा सकता है, जैसे टमाटर के बीजों को 6 घंटे तक 29-37 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाये तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस का असर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि टमाटर की बीजों को 46 डिग्री सेल्सियस गर्म वायु में 2 मिनट तक रखा जाये तो मोजेक रोग का प्रकोप कम होता है।

विकिरण द्वारा : इस विधि में विभिन्न तीव्रता की अल्ट्रावयलेट या एक्स किरणों को अलग-अलग समय तक बीजों पर गुजारा जाता है, जिससे रोगजनक नष्ट हो जाते हैं।

रासायनिक बीजोपचार: इस विधि में रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये दैनिक या अदैहिक फफूंदनाशक बीज के अंदर अवशोषित होकर अंत: बीज जनित रोगाणुओं को नष्ट करते है या यह एक संरक्षक कवच के रूप में बीज के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं, जिससे बीज पर रोगाणुओं का संक्रमण नहीं हो पाता। फफूंदनाशक को बीजोपचार के रूप में सर्वप्रथम 1760 में प्रयोग किया गया। शुल्त्येश ने सर्वप्रथम गेहूँ के कंडव रोग से बचाने हेतु कॉपर का प्रयोग किया। 1913 में रहिने ने आर्गेनिक परायुक्त फफूंदनाशक को बीजोपचार के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी। सन 1914 में हैरिंगटन ने घास (भान) रोक की रोकथाम के लिए थाइरम का उपयोग किया। सन 1952 में कैप्टन को बीजरक्षक फफूंदनाशक के रूप में उपयोग किया गया। सन 1968 में बेनोमिल की सर्वांगी फफूंदनाशक के रूप में खोज के पश्चात इस क्षेत्र एक नए युग की शुरुआत हुई। तत्पश्चात कार्बोकिसन, मेटालेक्सिन व दूसरे सर्वांगी फफूंदनाशक जैसे-थायरम, कैप्टान, एग्रोसान, डायथेम एम -45, डायफोलेटॉन की 2.5 से 3.0 ग्राम मात्रा, जबकि दैहिक फफूंदनाशकों जैसे-कार्बोन्डोजिम, बीटावैक्स, वेनलेट, बेनोमिल की 1.5 से 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होती है।

फफूंदनाशक दवाओं से बीजोपचार मुख्यत: निम्न विधियों से किया जाता है

सूखा उपचार : यह विधि सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली, उड़द, मूंग, अरहर, सूर्यमुखी, गेहूँ, चना, अलसी, सरसों आदि के लिए उपयुक्त हैं। बीजोपचार के लिए बीज तथा फफूंदनाशक दवा की उपयुक्त मात्रा को बीजोपचार ड्रम या मिट्टी के घड़े में डालकर 10 मिनट तक घुमाते हैं।

गीला उपचार : यह विधि प्राय: ऐसी फसलों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिसके कंद तथा तना आदि बीज के रूप में प्रयोग किये जाते है, जैसे गन्ना, आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, अरबी आदि। बीजोपचार के लिए आवश्यक मात्रा में पानी व दवा का घोल बनाकर उसमें 10 मिनट तक बीज को डुबाकर रखते हैं, फिर बोनी करते है।

स्लीरी विधि : यह एक व्यापारिक विधि हैं, जिसमें बड़े स्तर पर बीजोपचार करते हैं। इस विधि में कवकनाशी की निर्धारित मात्रा का गाढ़ा पेस्ट बनाकर, बीज की मात्रा के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है व अच्छी तरह सुखाने के पश्चात बीज को बेचने के लिए पैक कर संग्रहित करते हैं।

धुमिकरण : बीजजन्य रोगों के नियंत्रण हेतु यह एक अच्छी विधि है। इस विधि में सोयाबीन के बीजों को फामेल्डिहाइट के साथ 2 घंटे तक या हाइड्रोजाइक अम्ल को 53 घंटे तक धुमिकृत करने से 80 प्रतिशत तक जीवाणु मुक्त मिलते हैं।

दीमक से बीजों को बचाने हेतु कीटनाशी के रूप में क्लोरपाईरीफॉस 3-7 मि.ली. प्रति किलो बीज की दर से उपचार कर बीजों को लगाना चाहिए।

जैविक बीजोपचार : यह कवकीय या जीवाणुवीय उत्पति के होते हैं, जो कि पीथियम, राईजोक्टोनिया, फाइटोपथोर स्केलेरोशियम, मैक्रोफोमिना इत्यादि से होने वाली विभिन्न बीमारियों, जैसे-जड़ गलन, आर्द्रगलन, उकठा, बीज सड़न, अंगमारी आदि को नियंत्रित करते है। जैव नियंत्रण, हानिकारक कवकों के लिए या तो स्थान, पोषक पदार्थ, जल, हवा की कमी कर देते हैं या फिर रोगजनक के शरीर से चिपककर उसकी बाहरी परत को उपयोग कर लेते हैं, जिससे रोककारक जीव नष्ट हो जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति, बैसिलय सबटिलिस, स्यूडोमोनास प्रजाति, ग्लोमस प्रजाति प्रमुख जैव नियंत्रण है, जिनकी 4-5 ग्राम मात्रा बीजोपचार के लिए पर्याप्त है।

बीज भंडारण

- गोदाम, जहां बीज को रखना हो, स्वच्छ रहे, नियंत्रित रोशनदान हो, ऊँचा प्लिंथ हो, जिसमें नमी न आ सके तथा चिड़ियों के आक्रमण से भी सुरक्षित रहें।

-बीज रखने से पूर्व गोदाम को 1:300 के अनुपात में 3 लीटर प्रति 100 वर्गमीटर की दर से मालाथियान (50 ई.सी.) को छिड़ककर रोगाणुओं से मुक्त कर लें।

-बीज रखने के लिए अगर पुराने कपड़े के थैलों का प्रयोग करें तो उन्हें एलुमिनियम फॉस्फाइट से धूमित कर लें।

-बीज को 30' 20' के मानक आकार के टैंक पर रखें, जिससे उन पर गैस प्रूफ पोलीथिन के आवरण रखना तथा धूमित करना आसान हो।

-बीज रखने के पूर्णत: संतुष्ट हो लें कि बीज में अधिक नमी, जीवाणु और रोगाणु नहीं है।

-एक निश्चित समय पर बीज की देख-रेख अवश्य करें और निम्नलिखित तरीको का पालन करें।

(क) मालाथियान का 1:300 के अनुपात में घोल तैयार कर 3 लीटर प्रति 1000 वर्गफीट के दर से हर तीन सप्ताह बाद छिड़काव करें।

(ख) मालाथियान के साथ ही सुमिथियान का घोल भी 1:900 के अनुपात में तैयार कर 2-3 बाद छिड़काव करना लाभदायक है।

(ग) डी.डी.बी.पी. या नुवान या वापोना का 0.25 प्रतिशत घोल तैयार कर 1 लीटर प्रति 200 घनमीटर की दर से इस भांति छिड़काव करें कि गोदाम के सारे वातावरण में दवा की गंध भर जाये।

(घ) धूमिकरण: वायु की कमी वाली स्थिति या गैस प्रूफ आवरण में धूमी करण करना हो तो ऐलुमिनियम फॉस्फाइट की एक टिकिया (वजन तीन ग्राम) प्रति टन बीज की दर से व्यवहार करें। वायु का दबाव अधिक होने पर दो टिकिया का व्यवहार किया जा सकता है। धूमाकरण 60 दिनों के अंतर पर अधिक से अधिक तीन बार किया जाये। धूमीकरण के 4 दिनों के बाद ही गोदाम खोलना चाहिए और कम से कम 6 घंटे तक खिड़की-दरवाजा खुला रखकर हवा लगा लें। धूमीकरण के पहले रोगरोधी दवाओं का छिड़काव भी उपयुक्त रीति से आवश्यक है।

महाराष्ट्र सरकार ने चने और अरहर की खरीदारी बंद की

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी के तहत चने और अरहर (तुअर) की खरीदारी रोकने का फैसला किया है। गोदामों में पर्याप्त जगह नहीं होने और पैकेजिंग की दिक्कत के कारण राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। किसानों से सीधे खरीदारी की जगह अब सरकार भावांतर योजना के तहत चने और अरहर की खरीदारी करेगी। इसके तहत बाजार भाव और एमएसपी के बीच के अंतर को सरकार सीधे किसान को देगी।

अरहर की खरीद पूरे हुए बिना खरीद केंद्रों के बंद होने से किसानों में बढ़ते रोष को देखते हुए राज्य सरकार केंद्र सरकार से खरीद की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल, नेफेड तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में चने और अरहर की खरीद, उसके स्टॉक तथा पैकेजिंग और इसके सार्वजनिक वितरण केंद्रों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकारी गोदामों में भारी स्टॉक के कारण सरकार ने फैसला लिया है कि चने और अरहर की सरकारी खरीद बंद की जाएगी, लेकिन किसानों को नुकसान से बचाने के लिए चने और अरहर में प्रति क्विंटल 1,000 रुपये सरकार किसानों के खाते में सीधे जमा कराएगी।

महाराष्ट्र के विपणन मंत्री सुभाष देशमुख ने बताया कि राज्य में इस वर्ष एक फरवरी से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अरहर की खरीद शुरू की गई थी। खरीद की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने 15 मई तक इसकी मियाद बढ़ाई थी। इस साल अरहर खरीद का लक्ष्य 44 लाख क्विंटल था जिसमें 15 मई तक 193 खरीद केंद्रों पर 33,15,132 क्विंटल अरहर की खरीद की गई।

मुंबई में पानी हुआ महंगा, शविसेना ने तोड़ दिया वादा

मुंबई (कासं)। पानी की किल्लत से जूझ रहे मुंबई के लोगों को अब पानी पीने के लिए अधिक रकम अदा करना पड़ेगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पानी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। महानगर में पानी 3.72 प्रतिशत महंगा हो गया है। बीएमसी चुनाव के दौरान पानी की दरें कम करने की बात कहने वाली शिवसेना ने इस मामले में 'यू-टर्न' ले लिया है। स्थायी समिति की बैठक में पानी पर वर्ष 2012 में तैयार किया गया एक प्रस्ताव मंजूर हो गया, जिसमें पानी की दरों में इजाफा करने की मांग की गई थी। बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और समाजवादी पार्टी (एसपी) ने इसका विरोध किया। हालांकि समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव ने बहुमत के आधार पर मंजूरी दे दी। प्रति हजार लीटर 14 पैसे से 5.49 रुपये तक बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई दरों के मुताबिक, झोपड़पट्टी इलाके में पीने का पानी अब 3.82 रुपये प्रति हजार लीटर मिलेगा। पहले यह 3.68 रुपये था।

कृषि कंपनियों को मिलेगी धार

मुंबई (कासं)। इस सीजन में सामान्य मॉनसून के पूर्वानुमान के कारण बाजार की बढ़ती मांग पूरी करने के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान कृषि संबंधी सामान की कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने की उम्मीद है। 2018 की चौथी तिमाही के दौरान कच्चे माल की कीमतों में तीव्र वृद्धि और सीजन की कमजोर मांग के कारण कृषि संबंधी सामान की कंपनियों की बिक्री और लाभ पर भारी दबाव था। धानुका एग्रीटेक, पीआई इंडस्ट्रीज और रैलीस इंडिया जैसी कंपनियां ने 2018 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान अपनी बिक्री और लाभ में गिरावट दिखाई थी। युनाइटेड फॉस्फोरस ने मार्च 2018 की तिमाही के लिए कर उपरांत अपने लाभ में 35 फीसदी की गिरावट दर्ज की थी।

व्यापारियों और उपभोक्ताओं - दोनों ने ही कृषि संबंधी सामान की कीमतों में गिरावट की उम्मीद से बाजार की मांग के लिए स्टॉक निर्माण से दूरी बनाए रखी। इसके परिणामस्वरूप, पाइपलाइन स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया। अब, मॉनसून की बारिश की शुरुआत के बाद मांग का सीजन आरंभ होने के कारण कृषि संबंधी सामान की कंपनियों का सकल राजस्व और शुद्ध राजस्व जून तिमाही के मुकाबले सितंबर तिमाही में बेहतर होने जा रहा है। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एमके धानुका ने कहा कि मांग के इस सीजन में कृषि संबंधी सामान की कंपनियां अपने लाभ मार्जिन को बरकरार रखने के लिए कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं पर डालने में सक्षम दिखेंगी। इसकेअलावा, मॉनसून के मौजूदा सीजन में बारिश जून के अंत तक विस्तृत होती है। इसलिए जून तिमाही को कमजोर सीजन माना जाता है। मौसम का परिदृश्य सितंबर तिमाही के दौरान स्पष्ट होता है। इस वजह से बिक्री और लाभ के हिसाब से सितंबर तिमाही बेहतर होने की उम्मीद है।

मूंग की नई किस्म 'एचयूएम-16' विकसित

बांका (बिसं)। दलहन उत्पादन को दुरुस्त करने के लिए कृषि विभाग ने रबी फसल के बाद खाली खेतों के उपयोग का नया तरीका खोज निकाला है। इसके लिए किसानों को अत्याधुनिक तकनीक से शोध की गई नई किस्म एचयूएम-16 मूंग के बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके जरिए किसान मूंग का बढ़िया उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए अनुदान की योजना भी चलाई जा रही है। जिससे एक एकड़ में चार क्विंटल मूंग का उत्पादन हो रहा है। जिला में यह योजना कृषि अनुसंधान परिषद व सबौर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से चल रहा है।

हरित क्रांति के जरिये अभियान चला कर धान एवं गेहूं के फसल में क्षेत्र को आत्म निर्भर बनाने बाद सरकार ने तेलहन व दलहन की खेती में किसानों को आत्म निर्भर बनाने की कवायद शुरु की है। इसके तहत किसानों का समूह बना कर उसके खेतों की मिट्टी जांच के बाद वहां मूंग का प्रत्यक्षण किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाने के साथ ही उन्हें बीजोपचार, खर पतवार नियंत्रण, समेकित पोषण प्रबंधन, कीट व रोग प्रबंधन की तकनीक बताई जा रही है।

'डॉक्टरों के लिए सरकार बनाए लुभावनी योजनाएं'

मुंबई (कासं)। मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह ऐसी योजनाएं बनाए, जिससे गांवों और आदिवासी इलाकों में डॉक्टरों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की हालत को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। न्यायाधीश एनएच पाटील और न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी ने यह निर्देश इस मामले में दायर अनेक याचिकाओं की सुनवाई पर दिया। इन याचिकाओं में आदिवासी इलाकों के बच्चों में कुपोषण संबंधी मुद्दों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इन इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की बेहद कमी है। अदालत ने कहा कि सही बात तो यह है कि इन जिलों में मेडिकल केंद्र या तो हैं ही नहीं और यदि हैं भी तो उनकी हालत बहुत शोचनीय है। न तो वहां डॉक्टर हैं और न ही दवाएं। अदालत का कहना था कि इन केंद्रों पर डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए सरकार को कुछ बेहतर योजनाएं शुरू करनी चाहिए।

निजी स्कूलों को अब नहीं मिलेगी सस्ती बिजली

मुंबई (कासं)। राज्य के निजी स्कूलों को मिलने वाली सस्ती बिजली अब नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, राज्य के निजी स्कूलों को सामाजिक दृष्टिकोण से बिजली के बिल में 9प्रश. विद्युत शुल्क माफी दी जाती थी, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा की जा रही नफाखोरी के बाद राज्य सरकार ने यह रियायत रद्द करने का फैसला लिया है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत शुल्क अधिनियम 1958 प्रावधान के तहत सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत निजी स्कूलों को विद्युत शुल्क में यह रियायत दी जा रही थी। अब यह अधिनियम रद्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 2016 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों अर्थात नगर पालिका, महानगरपालिका, जिला परिषद आदि द्वारा संचालित स्कूलों को ही विद्युत शुल्क में माफी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में राज्य में बड़े पैमाने पर निजी स्कूल खुले हैं।

किसानो के लिए ड्रोन एक वरदान

मुंबई। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के फायदे के बारे में बताया की ड्रोन कैसे कृषि के लिए कारगार है। अब किसानो के लिए ड्रोन बहुत फायदेमंद है और इसे किसानो द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इसका कारण है ड्रोन का आसानी से उड़ना और कृषि समस्याओं को ढूंढ निकालना। ड्रोन जैसे उड़ता है वह किसानो को वह स्थान दिखाता है जो किसानो को देखने की आवश्यकता है। ड्रोन के माध्यम, से किसानो को पूरे क्षेत्र में जाने के बजाये सीधा उर्वरक या फसल वाली जगह पर जाकर वह यह काम आसानी से कर सकते है।

Hindchem Corproation

AMINO+HUMIC SHINY BALLS
FERROUS SULPHATE19%
MAGNESIUM SULPHATE 9.6%
FERROUS EDTA12%
E.D.T.A. ACID
CAMPHOR
SODIUM BICARBONATE
EDTA DISODIUM
CITRIC ACID MONOHYDRATE
MANGANESE SULPHATE 30.5%
SULPHUR 90% -80WDG
BORON 20%
BRONOPOL 25%
PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

दूर नहीं होगा गन्ना किसानों का दुख!

मुंबई (कासं)। मुंबई के थोक बाजार में चीनी के दाम 29 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गए हैं। चीनी मिलों के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) के रूप में 29 रुपये प्रति किलोग्राम तय करने के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद ऐसा हुआ। उद्योग के अधिकारी ज्यादा दाम चाहते थे, क्योंकि भारत की चीनी की उत्पादन लागत तकरीबन 35 रुपये प्रति किलोग्राम होने का अनुमान है, जो उत्तर प्रदेश में 36 रुपये और महाराष्ट्र में 34 रुपये हो सकती है। हालांकि, यह एमएसपी अब भी मिलों के लिए चीनी की औसत उत्पादन लागत 35 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में 21 प्रतिशत कम है। मिलों द्वारा किसानों को अदा किए जाने वाले गन्ने के उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) के मद्देनजर ये दाम रंगराजन समिति के फॉर्मूले के हिसाब से चीनी के उचित मूल्य की तुलना में 23.5 फीसदी कम है। इस कारण उद्योग को लग रहा है कि मिलों द्वारा किसानों का बकाया चुकाना मुश्किल होगा। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा का कहना है कि मिलों को किसानों का बकाया भुगतान करना मुश्किल लगेगा। बाजार के हालात और सभी प्रोत्साहनों को ध्यान में रखने के बावजूद, बड़ा बकाया बिना भुगतान के रह सकता है। सरकार मिलों के लिए एमएसपी में 35 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा कर सकती थी, जिसके लिए अतिरिक्त सब्सिडी का व्यय नहीं होता। उपभोक्ता मूल्य बढ़ सकता था, लेकिन चीनी की अधिकता के इस परिदृश्य में उपभोक्ताओं के लिए दाम सीमित रहते। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी के अनुसार, मिलें करीब 23.50-24 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक्री कर रही थीं और आज उन्होंने 29 रुपये पर बिक्री की, जो एमएसपी है। इस प्रकार, एमएसपी ने उनके लिए 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम की अधिक आमदनी सुनिश्चित कर दी।

कपास निर्यात रहेगा 4 साल में सबसे अधिक

मुंबई (कासं)। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कपास की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और अमेरिका एवं चीन जैसे प्रमुख कपास उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम से भारत के कपास निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीदें जगी हैं। विश्लेषक और कारोबारी जगत कपास वर्ष (अक्टूबर से सितंबर) 2017-18 के लिए निर्यात के अनुमानों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब कपास का निर्यात 75 लाख गांठों पर पहुंचने का अनुमान है, जो 2013-14 के बाद सबसे अधिक है। निर्यातकों का मार्जिन भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस समय निर्यात हो रहे कपास की एफओबी कीमत 83.78 सेंट है, जबकि अमेरिका के बेंचमार्क आईसीई फ्यूचर में कपास की कीमत 89 से 90 सेंट है। एक निर्यातक ने कहा कि पहले इतना मार्जिन कभी नहीं मिला। वह सूती धागे के निर्यात पर ध्यान दे रहे हैं, जिसे कपास के विकल्प के रूप में तरजीह दी जा रही है। इसकी वजह यह है कि पिंक बॉलवर्म के प्रकोप की वजह से इस सीजन में भारत के कपास की गुणवत्ता अव्वल दर्जे की नहीं थी। मार्च में सूती धागे का निर्यात 15.8 करोड़ किलोग्राम रहा, जो दिसंबर, 2016 के बाद सर्वाधिक है। एडलवाइस एग्री सर्विसेज ऐंड क्रेडिट की शोध प्रमुख प्रेरणा देसाई ने कहा, चालू कपास सीजन में भारतीय कपास के दाम लगातार कमजोर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह पिंक बॉलवर्म से फसल को नुकसान की शुरुआती खबरें थीं। वैश्विक कीमतों में भारी बढ़ोतरी और भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भारतीय कपास की वैश्विक बाजारों में मुकाबले की क्षमता में इजाफा हुआ है। इससे कपास का ज्यादा निर्यात होगा। चालू सीजन में अक्टूबर से अप्रैल तक भारत से करीब 61 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किलोग्राम) का निर्यात हुआ है। यह पूरे वर्ष में बढ़कर 70 से 75 लाख गांठ तक पहुंच सकता है। कमजोर रुपये से सूती कपड़े की मूल्य शृंखला के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे सीजन की शेष अवधि में कपास की कीमतों को सहारा मिलेगा।

कपास की कीमतें बढ़ने की वजह यह है कि कुछ सप्ताह पहले चीन के मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्रों में बारिश हुई है और उसका कपास भंडार घटकर 3 साल पहले के मुकाबले महज 20 फीसदी रह गया है। इस वजह से चीन में घरेलू आपूर्ति गिर रही है। अमेरिका कपास की मांग है।

मैदानी क्षेत्रों के लिए आलू की तीन नई किस्में विकसित

शिमला (विसं)। केंद्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, शिमला के मोदीपुरम केंद्र ने भोज्य आलू की तीन नई किस्में कुफरी गंगा, कुफरी नीलकंठ व कुफरी लीमा का विकास किया है। नई किस्मों का विकास, संस्थान द्वारा पिछले 10-12 लम्बे अनुसन्धान एवं कड़े परीक्षणों के फलस्वरूप हुआ है। नई किस्में, मैदानी क्षेत्रों में उगाई जा रही परिचालित किस्मों से अधिक उपजाऊ हैं एवं अन्य गुणों में भी बेहतर पाई गयी हैं।

कुफरी गंगा: यह किस्म मुख्य फसल में लगाने के लिए उपयुक्त हैं। इसके कंद सुन्दर सफ़ेद-क्रीम, अंडाकार, उथली आखें व गूदा क्रीम होता है। इसमें पछेती झुलसा रोग से सामान्य प्रतिरोधकता है व इसकी भण्डारण क्षमता अच्छी हैं। यह भोज्य आलू के लिए उपयुक्त हैं। इस किस्म से लगभग 35-40 टन प्रति हैक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। कुफरी गंगा में शुष्क पदार्थ की मात्रा 16-18प्रश. होती है। यह कम पानी में भी अन्य किस्मों के मुकाबले अधिक उत्पादन देने में समर्थ है।

कुफरी नीलकंठ: यह मुख्य फसल में लगाने के लिए भोज्य आलू की विशेष किस्म है। इसके कंद सुन्दर बैंगनी, अंडाकार, उथली आखें व गूदा पीला होता है। सेहत के दृष्टिकोण से इस किस्म में एंटी-ऑक्सिडेंट (एन्थो-सायनीन व करोटीनोइड्स) की मात्रा अन्य लाल रंग वाली किस्मों से अधिक है। इसमें पछेती झुलसा रोग से सामान्य प्रतिरोधकता है व इसकी भण्डारण क्षमता भी अच्छी है। इस किस्म से लगभग 35-38 टन प्रति हैक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। कुफरी नीलकंठ में शुष्क पदार्थ की मात्रा 17-18 प्रश. होती है।

कुफरी लीमा : अगेती फसल में लगाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि एवं इसमें अधिक तापमान के साथ-साथ हॉपर व माईट कीटों के प्रति सहनशीलता भी है। इसके कंद सुन्दर सफ़ेद-क्रीम, अंडाकार, उथली आखें व गूदा क्रीम होता है। इसकी भण्डारण क्षमता अच्छी है तथा यह भोज्य आलू के लिए उपयुक्त है। इस किस्म से लगभग 30-35 टन प्रति हैक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अगेती आलू फसल के ताजा उत्पाद की सर्दिओं के त्यौहारी दिनों में अच्छी मांग के कारण मुनाफा भी अधिक मिलता है। कुफरी लीमा में शुष्क पदार्थ की मात्रा 18-19प्रश. होती है।

इन किस्मों के अपनाने से किसानों के उत्पादन व आय में वृद्धि होगी साथ ही विशेषकर बैंगनी रंग वाली किस्म कुफरी नीलकंठ से उपभोक्ताओं को अच्छा पोषण भी मिलेगा।

कृषि के लिए मुफ्त बिजली की सिफारिश

चंडीगढ (कासं)। पंजाब राज्य कृषक और कृषि मजदूर आयोग ने हाल में जो कृषि नीति का मसौदा तैयार किया है, वह प्रदेश सरकार के इस इरादे को बताता है कि कृषि क्षेत्र में वह पानी और बिजली दोनों बचाना चाहती है। आयोग की राय है कि बडे किसानों को रियायती बिजली पूरी तरह बंद की जाए और अंधाधुंध पानी के दोहन को रोकने के लिए रियायती बिजली की आपूर्ति को भी लगाम दी जाए। आम लोगों की राय के लिए रखे गए आयोग के पंजाब राज्य किसान नीति के मसौदे में कहा गया हैं कि रियायती बिजली गैर आयकरदाता किसानों तक ही सीमित रखी जाए। रियायती बिजली की आपूर्ति पर लगाम के लिए मसौदे में सुझाव दिया गया है कि चार हैक्टेयर या उससे अधिक भूमि वाले किसानों पर प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिमाह सौ रूपए का शुल्क लगाया जाए। इसके बाद बिजली आपूर्ति पर अनुदान की वित्तीय सीमा तय की जाए। आयोग के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ के अनुसार किसान संगठन इस बात पर सहमत है कि बडे किसानों का बिजली अनुदान रोक दिया जाए।

महाराष्ट्र में आपातकाल में जेल गए सभी लोगों को मिलेगी मासिक पेंशन

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने करीब 40 साल पहले आपातकाल में एक माह से अधिक समय तक जेल में रहे लोगों को दस हजार रुपये की मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। यह पेंशन योजना भाजपा की प्रमुख योजनाओं में से एक होगी। बुधवार को कैबिनेट की उप समिति ने एक माह से कम समय तक जेल में कैद रहे लोगों को पांच हजार रुपये की मासिक पेंशन देने का फैसला किया है।

वैज्ञानिक तरीके से खेती कर किसान उठाएं लाभ

करपी (अरवल) (विसं)। प्रखंड क्षेत्र की नरगा पंचायत के नादी ग्राम में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया सुधीर कुमार ने की। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्रीनिवास सिन्हा ने कहा कि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अधिक लाभ कमाएं. सरकार किसानों को लिए कृषि आधारित कई योजनाएं चला रही है। उन योजनाओं का किसान लाभ प्राप्त करें। कृषि यांत्रिकरण, श्री विधि से खेती, बीज ग्राम योजना, समूह गठन कर खेती, जैविक खेती, मछली पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी पदाधिकारियों ने किसानों को दी गयी।

देसी गाय के गोबर व गोमूत्र से खेती कर कमा रहा कम पैदावार पर भी ज्यादा मुनाफा

चरखी दादरी (विसं)। जिले के गांव अटेला का किसान पिछले छह साल से जैविक खेती कर रहा है। इस बार किसान ने जैविक खाद से तैयार कर गेहूं 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बेचा है, जबकि गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य 1735 रुपये प्रति क्विंटल है। किसान अपने घर पर ही गाय के गोबर से जैविक खाद तैयार कर प्रति एकड़ 55 हजार रुपये कमा रहा है। किसान दीवान सिंह ने बताया कि जैविक खेती में भले ही पैदावार कम हो लेकिन मुनाफा सामान्य खेती से अधिक होता है। जैविक उत्पाद की मांग दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है कि किसान लोगों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बरसों पुरानी परंपरा को अपना कर जिले के कुछ किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। किसान अब रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक पद्धति को अपनाने लगे हैं। जिला के गांव अटेला निवासी सफल किसान दीवान सिंह ने 2012 में जैविक खेती शुरू की थी। उस समय उन्होंने एक एकड़ में जैविक रूप से गेहूं की फसल उगाई थी। दीवान सिंह आज करीब नौ एकड़ भूमि में जैविक खेती कर रहे हैं। सफल किसान दीवान का कहना है कि जैविक खेती के लिए शुरूआत में ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है।

कपास की फसल पर कीट और पानी की मार

अहमदाबाद (विसं)। पिंक बॉलवर्म कीट के संक्रमण की परेशानी के कारण कपास के बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल बुआई प्रभावित हो सकती है। पानी की भारी किल्लत एक अन्य बाधा रहेगी। व्यापारिक सूत्रों ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में भी ऐसी आशंका से इनकार नहीं किय है। बड़ी चिंता इस बात से है कि मॉनसून शुरू हो चुका है और खासकर महाराष्ट्र में इसमें रुकावट आई है। पिछले दो सालों में कई इलाकों में पिंक बॉलवर्म फसल बरबाद कर चुका है और यहां तक कि बीटी कपास भी इससे सुरक्षित नहीं है। अगर मॉनसून की कुछ शुरुआत होने के बाद इसमें विलंब हो तो ऐसे में कपास बुआई कीट के हमले की दृष्टि से असुरक्षित होती है। इस महीने के पहले सप्ताह में कपास की बुआई तीन साल के सामान्य औसत के 0.37 प्रतिशत या 9,339 हेक्टेयर पर ही पहुंच पाई है। 2017 में समान अवधि के दौरान यह 49,400 हेक्टेयर और 2016 में 15,200 हेक्टेयर थी। दरअसल, बॉलवर्म के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए राज्य सरकार ने खुद ही किसानों को बाद में (मॉनसून शुरू होने के बाद) बुआई करने की सलाह दी है। पिछले चार सालों में बॉलवर्म के संक्रमण ने गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में कपास की खेती को नुकसान पहुंचाया है। गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव कॉटन फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन हसमुख रावल कहते हैं, गुजरात में कपास की खेती का एक बड़ा क्षेत्र पानी की भारी किल्लत का सामना कर रह है। अगर बारिश होती है और किसी को पर्याप्त पानी मिलता है, तो ही बुआई शुरू हो सकती है। बुआई में कम से कम 20 प्रतिशत तक की गिरावट आने की संभावना है। इस खरीफ सीजन में कपास की बुआई में 10 प्रतिशत गिरावट के आसार हैं। कीट आक्रमण की दृष्टि से असुरक्षित कुछ इलाकों में भी सरकार ने किसानों को कपास की शीघ्र बुआई नहीं करने का सुझाव दिया है, जैसा कि वे गेहूं की फसल कटाई के बाद किया करते थे।

यू एस एग्रोकेम प्रा.लि.
Wholesale Supplier
सूक्ष्म तत्व मिश्रण तरल एवं दानेदार

व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है

प्लाट नं. बी-81, 82, नीलगिरी कॉलोनी, रोड नं. 9 के सामने, वीकेआई एरिया, जयपुर-302013 (राजस्थान)
E-mail : suresh@hindchem.com, Contact : 9004744077

कैसे करें धान की आधुनिक व उन्नत खेती?

धान सम्पूर्ण विश्व में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। प्रमुख खाद्यान्न चावल इसी से प्राप्त होता है। धान भारत सहित, एशिया और विश्व के अधिकांश देशों का मुख्य खाद्य है। मक्का के बाद धान की फसल ही मुख्य रूप से विश्व में बड़े पैमाने पर उत्पन्न की जाती है। किसी अन्य खाद्यान्न की अपेक्षा धान की खपत विश्व में सर्वाधिक है। चीन के बाद भारत का चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। धान की अच्छी उपज के लिए 100 सेमी. वर्षा की आवश्यक होती है।

खेत की तैयारी: किसान भाइयों गरमी के मौसम में सही समय पर खेत की गहरी जुताई हल या प्लाउ चला कर करें, जिस से मिट्टी उलटपलट जाए। मेंड़ों की सफाई जरूर करें। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई या बारिश से पहले खेत में फैला कर मिलाएं।

बीजोपचार: बीज को थायरम या डायथेन एम 45 दवा 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बुवाई करें। बैक्टेरियल बीमारियों के बचाव के लिये बीजों को 0.02 प्रतिशत स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में डुबाकर उपचारित करना लाभप्रद होता है।

धान की खेती के प्रकार

निचली मृदाओं में धान की खेती

लेहयुक्त मृदाओं में खेती

धान के खेत में लेह के लाभ-

-खेत से खरपतवारों को नष्ट करने एवं उनको लेहयुक्त सतह में दबाने में सहायक है।

-धान की फसल की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं को उपयुक्त बनाती है।

-भूमि की सतह अधिक समतल हो जाती है।

-लेह लगाने से, लीचिंग द्वारा होने वाली पोषक तत्वों की हानि कम होती है।

-खेत में रोपण विधि या पौध विधि-

पौध विधि : ऐसी मृदाओं में अधिकतर पौधे लगाकर ही धान की खेती करते हैं। पौध लगाने के लिए छोटी-छोटी क्यारियां (बीज शैयाओं) की आश्यकता होती है। बीज शैया के लिये ऐसी भूमि छाँटनी चाहिए जहां पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो।

पौध तैयार करना- पौध उपजाऊ, जल निकास वाले खेत में उगानी चाहिये जो कि सिंचाई के साधन के पास हो। एक हैक्टेयर रोपाई के लिये 500 वर्ग मीटर पौध क्षेत्र (एक हेक्टेयर का बीसवां भाग) पर्याप्त होता है। धान की पौध के लिये जया, आई.आर. 8, मध्यम देर से पकने वाली किस्मों; जैसे- रत्ना, आई.आर. 24, कावेरी, साकेत 4, आदि की बुवाई 15 जून के आसपास करनी चाहिए।

धान की पौध तैयार करने की निम्नलिखित विधियां हैं-

भीगी विधि : इस विधि द्वारा पौध तैयार करने के लिये खेत में पानी भरकर दो या तीन बार जुताई कीजिए ताकि मिट्टी लेहयुक्त हो जाये तथा खरपतवार नष्ट हो जायें। आखरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिये। इसके एक दिन बाद जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तब खेत को सवा से डेढ़ मीटर चौडी तथा सुविधाजनक लंबी क्यारियों में बांट लीजिए ताकि बुवाई, निराई, सिंचाई आदि कियाएं आसानी से की जा सकें। बीज दर प्रति 10 वर्ग मीटर (8 × 1.25 वर्ग मीटर) जया, आर. आई. 8, आदि मोटे दाने वाली किस्मों में 800 ग्राम से एक किग्रा तथा साकेत 4 वा आई.आर. 24 आदि पतले दाने वाली किस्में 500 ग्राम से 750 ग्रामरखना चाहिए। बोने से पहले प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 225 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सुपर फॉस्फेट अच्छी तरह मिला लेना चाहिए। अंकुरित बीजों को समान रुप से बिखेर देना चाहिये। वर्षा के कारण अगर बीज पानी में डूब जाये तथा धूप रहे तो पानी निकाल देना चाहिये ऐसा ना करने पर बीज सड़ जायेगा। आवश्यकतानुसार निराई, सिंचाई, रोगों तथा कीड़ों

की रोकथाम आदि का उचित प्रबंध करना चाहिए।

शुष्क विधि : अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क विधि अपनानी चाहिये। अगर लगातार वर्षा कम होती है तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी यह विधि उपयुक्त है। इसमें खेत को शुष्क या नम अवस्था में तैयार करते हैं। 3-4 बार जुताई कर मिट्टी भुरभुरी बना ली जाती है। खेत को समतल कर भीगी विधि में दिये गये आकार के अनुसार 20 सेमी ऊँची क्यारियां बनानी चाहिये तथा मेड़ की जगह 30 सेमी चौड़ी नाली बनानी चाहिये। सूखे बीज को 10 सेमी की दूरी पर लाइनों में 2 सेमी गहरा बो देना चाहिये। बीज, खाद आदि की मात्रा भीगी विधि के अनुसार ही प्रयोग करनी चाहिये।

डैपोग विधि : पौधे उगाने की तीसरी विधि डैपोग है जो फिलीपीन्स में प्रचलित है। इस विधि में पौध को बिना मृदा के उगाते हैं। बीज को 10-12 घंटे तक पानी में भिगोकर बाद में निकालकर इसको नम रखकर अंकुरित किया जाता है। अंकुरित बीजों को 0.5 सेमी मोटी तह, सीमेंट के फर्श पर फैलाकर ऊपर से इसे पॉलिथीन के चद्दर या पुआल पत्तियों (5 सेमी) से ढक दिया जाता है। लगातार इसकी भी नम बनाये रखते हैं। प्रारंभ में इसकी सुरक्षा चिड़ियों वगैरह से भी रखनी पड़ती है। पौध तैयार करने में उर्वरक व खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पौध तैयार करने में उर्वरक व खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। पौध 10-15 दिन में तैयार हो जाती है।

-बीज शैय्या से पौधे उखाड़ते समय समय खेत का नम होना आवश्यक है जिससे कि पौध को उखाड़ते समय जड़ें न टूटने पायें। पौध की खेत में रोपाई 3 सेमी की गहराई पर करते हैं। डैपोग विधि से उगाई गई पौध से एक साथ 3-4 पौधे रोपते हैं। पौध रोपने के बाद खेत में 4-5 सेमी. पानी रहना आवश्यक है।

रोपाई : जब पौध 20-25 दिन की हो जाये तो रोपाई कर देनी चाहिये। अच्छी तरह लेह लगाकर जुताई किये गये खेत में 20 × 30 सेमी. दूरी पर दो पौधों को रोपना चाहिये। पौध को 2 3 सेमी. से ज्यादा गहरा नहीं रोपना चाहिए रोपते समय खेत में पानी की पतली तह होनी चाहिये ताकि पौध को उथला रोपा जा सके। पौध पुरानी हो जाने पर एक स्थान पर 4-5 पौधे रोपे जाने चाहिये।

सीधे खेत की बुआई विधि: लेहयुक्त मृदाओं में पौधरोपण के स्थान पर अंकुरित बीजों को खेत में छिटककर अथवा पंक्तियों में बो सकते हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर लेह, वर्षा से 2 सप्ताह पहले लगाकर भी इस प्रकार की बुवाई कर सकते हैं। अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो वर्षा आरंभ होने पर ही खेत में बुवाई करते हैं। छिटकवाँ विधि से 100-120 किग्रा बीज व पंक्तियों में 20 सेमी. की दूरी पर बने से 60-80 किग्रा बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभ में खेत में 1 सेमी. पानी खड़ा रखते हैं लेकिन बाद में जैसे-जैसे फसल बढ़ती है खेत में पानी 2-5 सेमी. खड़ा रख सकते हैं।

धान की रोपाई एवं बुवाई का समय: उत्तरी भारत में अधिकतर जून-जुलाई में धान की रोपाई होती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में धान की फसल बोने और काटने के लिये समयानुसार धान की फसलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है-

-अपने देश में वर्षाकालीन फसल अधिकतर क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस समय में अधिकतर लंबी अवधि वाली जातियां उगाई जाती हैं। अगेती (ओटम या ओस) फसल की खेती; ऊंची भूमियों पर की जाती है। इस फसल में 90-110 दिन की अवधि वाली जातियाँ उगाते हैं। धान की ग्रीष्मकालीन फसल कुछ क्षेत्रों में ही ऊगा पाते हैं। शीघ्र तैयार होने वाली जातियाँ इस समय उगाते हैं।

खाद एवं उर्वरक की मात्रा:

गोबर की खाद या कम्पोस्ट : धान की फसल में 5 से 10 टन/ हेक्टेयर तक अच्छी सड़ी गोबर खाद या कम्पोस्ट का उपयोग करने से महंगे उर्वरकों के उपयोग में बचत की जा सकती है। हर वर्ष इसकी पर्याप्त उपलब्धता न होने पर कम से कम एक वर्ष के अंतर से इसका उपयोग करना बहुत लाभप्रद होता है।

हरी खाद का उपयोग : रोपाई वाली धान में हरी खात के उपयोग में सरलता होती है, क्योंकि मचैआ करते समय इसे मिट्टी में आसानी से बिना अतिरिक्त व्यय के मिलाया जा सकता है। हरी खाद के लिए सनई का लगभग 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रोपाई के एक महीना पहले बोना चाहिए। लगभग एक महीने की खड़ी सनई की फसल को खेत में मचैआ करते समय मिला देना चाहिए। यह 3-4 दिनों में सड़ जाती है। ऐसा करने से लगभग 50-60 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की बचत होगी।

उर्वरक : बोनी जातियों के लिए 120 किग्रा, नाइट्रोजन, 60 ग्रा फॉस्फोरस, 50 किग्रा पोटाश प्रति हैक्टेयर, किग्रा देशी जातियों के लिए 60 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फॉस्फोरस, 30 किग्रा पोटाश प्रति हैक्टेयर।

-पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 80 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किग्रा फास्फोरस व 40 किग्रा पोटाश प्रति हैक्टेयर देना चाहिए।

-नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा आखिरी बार लेह लगाते समय एकसमान बिखेरकर ऊपरी 15 सेमी मिट्टी में अच्छी प्रकार मिला देनी चाहिये। नाइट्रोजन की शेष मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिये, पहली टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 20-30दिन बाद, दूसरी टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 50-60 दिन बाद करनी चाहिये। किसी भी अवस्था में खाद डालते समय खेत में अधिक पानी खड़ा नहीं होना चाहिए।

-यदि फसल में जस्ते की कमी के लक्षण पिछले वर्ष देखे गये हैं तो उन खेतों में 25-30 किग्रा जिंक सल्फेट बुवाई के समय ही दें। यदि ऐसा नहीं है तो कमी के उपरोक्त लक्षण दिखाई देने पर 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 किग्रा यूरिया को 100 लीटर पानी में घोलकर (आवश्यकतानुसार इसी अनुपात में बनाकर) एक-एक सप्ताह बाद 2-3 बार लगातार छिड़काव करें। इस बात का ध्यान रखा जाये कि धान में जैसे ही फसल में लोहे की कमी के लक्षण देखे गये हैं तो फैरस सल्फेट के 1.0प्रश. घोल का छिड़काव एक सप्ताह के अन्तर पर 2-3 बार करें।

नीली हरी एलगी (काई) का धान के उत्पादन में महत्व-

नीले हरी एलगी की अधिकतर जातियां नत्रजन का मृदा में एकत्रीकरण करती हैं। नीली हरी एलगी की एक जाति टोलीपोथ्रिक्स टन्यूइस प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 20-30 किग्रा नत्रजन तक इकट्ठी कर सकती है। अत: इस एलगी से धान की उपज बढ़ाने के लिये विभिन्न उर्वरकों को इसके साथ खेत में देते हुए उपज पर प्रभाव देखा और पाया गया है-

-अकार्बनिक उर्वरक एलगी के साथ खेत में दिए जा सकते हैं। एलगी के नत्रजन एकत्रीकरण पर इन उर्वरकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

धान की फसल में एलगी के साथ 80 किग्रा नत्रजन प्रति हेक्टेयर उर्वरक देने पर अच्छी उपज प्राप्त होती है। अत: निष्कर्ष निकलता है कि एलगी के द्वारा 40 किग्रा नत्रजन प्रति हैक्टेयर धान की फसल को प्राप्त हो जाती है। प्रयोग के अन्दर फॉस्फोरस व पोटाश रोपाई के समय ही खेत में दे दिये गये। सीधे बोये गये खेत में या असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन 60 किग्रा, फॉस्फोरस 30 व पोटाश 25 किग्रा प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई पर ही देते हैं।

-एलगी कुछ ऐसे जैविक पदार्थ (जैसे विटामिन व हार्मोन) बनाती है जो पौधों को स्वस्थ रखते हैं, नत्रजन आदि उर्वरकों की उपयोगिता बढ़ाती है, भूमि के गुणों में सुधार करती है। भूमि में सोडियम लवणों की मात्रा को कम करती है।

जल प्रबंध: रोपाई के दूसरे दिन हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बाद में जल स्तर 5 सेमी. तक कर देना चाहिये। साधारण अवस्था में दानों के थोड़े-थोड़े सख्त होने या कटाई के समय तक इस जल स्तर को बनाए रखिए। खरीफ में वर्षा के रुक जाने पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिये। यदि खेत की मिट्टी पानी से तर है तो खेत को पानी से पूरा भरने की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी खेत में भरा हुआ पानी घास-पात को बढ़ने से रोक देता है।

निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण: खरपतवारों की समस्या प्राय: ऊंची भूमियों में अधिक होती है। धान की खेती जिन क्षेत्रों में ऊंची मृदाओं में करते हैं, वहां पर अवसर मिलने पर 20-25 दिन बाद एक निराई-गुड़ाई खुर्पी की सहायता से कर देते हैं। दूसरी निराई की आवश्यकता पड़ने पर; रोपाई के 40-45 दिन बाद करते हैं।

धान के प्रमुख खरपतवार: साावां,मकरा, काँदों, मौथा, बानरा बनक, सफेद मुर्ग व भंगरा।

प्रमुख कीट:

धान की जड़ सूड़ी : इस कीट की गिडार उबले हुए चावल के समान होती हैं। यह कीट महीन जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और पौधे पीले पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए एल्डिन 30 ई.सी. या गामा बी.एच.सी. 30 या 10ल्र बिरलेन ग्रेन्यूल्स का प्रयोग करना चाहिए।

तना छेदक (धारीदार, गुलाबी, पीला, सफेद): इस कीट की गिडार ही नुकसान पहुंचाती हैं। फसल की प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रकोप से पौधों का मुख्य तना सूख जाता है।

खरीफ के टिड्डे: निम्फ और प्रौढ़ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के प्रकोप से पत्तियां किनारे पर कटी हुई मिलती हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु 10प्रश. बी.एच.सी. चूर्ण या इंडोसल्फान का प्रयोग करना चाहिए।

कटाई: कटाई विभिन्न जातियों 100 से 150 दिन में पककर तैयार होती हैं।बालियां निकलने के 25-30दिन बाद अधिकतर जातियाँ पक जाती हैं। दानों में दूध गाढ़ा, सख्त होने पर कटाई की जा सकती है। कटाई हंसिया आदि से करते हैं। शक्तिचालित यंत्रो से कटाई करने के लिए खेत पकने से पहले जल निकास करके खेत को सुखा लिया जाता है।

आंवला के बाग को कीड़ों से बचाये

आंवला अपने अद्वितीय औषधीय एवं पोषक गुणों के कारण भारतीय पौराणिक सहित्य में इस फल को जीवन दात्री अथवा अमृत फल के समान लाभकारी माना है। आँवला कम रख रखाव में भी अधिक उत्पादन एवं आय प्राप्त कराता है, तथा मुख्य फलों की तुलना में इसमें विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता अधिक होती है। आंवले की विषेषताऐं प्रति ईकाई उच्च उत्पादकता (15-20टन /हे.) विभिन्न प्रकार की बंजर भूमि (ऊसर, बीहड़, खादर, शुष्क , अर्धशुष्क) हेतु उपयुक्तता, पोषण एवं औषधीय गुणों से भरपूर तथा विभिन्न रूपों में उपयोगी। आंवला के विभिन्न भागों में विषेष औषधीय गुण होते है, आंवला त्रिदोष वात, पित, कफनाशक होता है, यह शरीर की त्वचा, सिर के बाल, नेत्रों की ज्योति, मुंह के दांत मसुड़े, कब्ज और पेट के पाचन तंत्र के लिये अत्यंत गुणकारी है।

प्रस्तुत लेख में आँवला में लगने वाले कीट एवं नियंत्रण के बारे में विस्तार में दिया जा रहा है।

कीड़े एवं नियंत्रण:- आँवला में लगने वाले कीट में छाल भक्षी/छालखाने वाली सुण्डी (इल्ली), शूट गाल मेकर , स्केल कीट (शल्क कीट) एवं दीमक मुख्य कीट माने जाते हैं।

छालभक्षी कीट/ छाल खाने वाला कीट: यह कीट जिन बागों की ठीक से देख-भाल नहीं होती, उनमें छालभक्षी कीट का इनडरबेला टेट्राओनिस का प्रकोप अधिक पाया जाता है। इस कीड़े की इल्ली तने एवं मुख्य शाखाओं में घुसकर छाल को खाते एवं छेद करते हैं। जिसकी पहचान प्ररोहों, शाखाओं एवं तनों पर बनायी गयी अनियमित सुरंगों से होती है, जो रेशमी जालों, जिसमें चबायी हुई छाल के टुकड़े छिद्र के पास बुरादे जैसा चाकलेटी रंग का अवशेष छोड़ता है और उनके मल सम्मिलित होते हैं, से ढकी होती है।

नियंत्रण: इस कीट के प्रकोप को रोकने के लिए छिद्र की सफाई करके छिद्रों में बारीक तार डालकर कीड़ों को मार देना चाहिए । अधिक प्रकोप होने पर सुरंगों एवं आवासीय छिद्रों को साफ कर रूई के फाये को 0.025 प्रतिषत डाइक्लोरवॉस के घोल में भिगो कर छिद्रों में या छिद्रों में एक भाग मेटासिस्टाक्स या डाईमिथोएट और 10 भाग मिट्टी का तेल मिलाकर और उसमें रूई भिगोकर छिद्रों में डालकर, गीली मिट्टी से छिद्रों बन्द कर देना चाहिए या 0.05 प्रतिषत मोनोक्रोटोफॉस या 0.05 प्रतिशत क्लोरपाइरीफॉस का घोल बनाकर छिद्रों में इन्जेक्शन वाली सूई द्वारा डाल कर गीली मिट्टी से बन्द कर देना चाहिए ।

शूट गाल मेकर: इसकी छोटी इल्लियाँ छोटे पौधों एवं पुराने फलदार वृक्षों की शाखाओं के शीर्ष भाग में छेदकर भीतर घुस जाती है, जिससे ग्रसित भाग फूल कर गॉल (पीटिका) या गाँठ के रूप में दिखाई देने लगता है। जिसमें काले रंग का कीड़ा पाया जाता है। प्रकोप के शुरूआत में तनों/प्ररोहों के अग्र भाग में सूजन सी आ जाती है जो समय के साथ - साथ बड़ी होकर पिटिका या गॉल का आकार ले लेती है। इसके गम्भीर प्रकोप अवस्था में पेड़ की शाखाओं का शीर्ष भाग बढ़ना बंद हो जाता है। जिससे पुष्पन और फलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

नियंत्रण: इस कीट के प्रकोप को रोकने के लिए मार्च के महीने में जब पेड़ की पत्तियाँ झड़ जायें उस समय गाल वाली प्ररोहों की पहचान आसानी से की जा सकती,। वैसे गाल (गांठ) वाली प्ररोहों को समय-समय पर काट कर कीड़ों को सहित जला देना चाहिए । काटकर गांठ के काटने पर पौधे की जो वृद्धि रूक गई हो वह पुन: शुरू हो जाती है। सूट गाल मेकर की मादा मई महीने में रात्रि के समय अण्डे देकर भाग जाती है। ऐसी दशा में 3 मि. ली. डाइमेक्रान/रोगर 10 ली. पानी में मिलाकर छिड़काव कर देने से अण्डे और गिडारें मर जाती हैं। जिन बागों में इसका लगातार प्रकोप होता है वहां मौसम के शुरूआत में मोनोक्रोटोफास या पैराथियान या मेटासिस्टाक्स कीटनाशक दवा का 10 से 20 मि. ली. दवा, 10 लीटर पानी में घोलकर, पौधे में अच्छा छिड़काव करना चाहिये, दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद किया जा सकता है। जुलाई-अगस्त में मोनोक्रोटोफोस 1.25 मि.ली. प्रति लीटर पानी या फास्फेमिडान 0.6 मि. ली. प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करके काफी हद तक क्षति को रोका जा सकता है।

शल्यकीट: आवंलें की पत्तियों में फरवरी-मार्च में यह कीट आक्रमण करता है। इस कीट की पहचान यह है कि उसमें पत्तों पर चीटें लगने लगते है। ये कीट सूक्ष्म तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। इनके झुंड के झुंड पत्तियों, टहनियों तथा फूलों पर चिपके रहते हैं और उनका रस चूसते हैं। सफेद रूई जैसे पदार्थ से ये कीट ढ़के रहते हैं। प्रौढ़ एवं षिषु कीट एक प्रकार का मीठा तरल पदार्थ निकालते हैं, जिससे काली फफूँदी से पत्तियों का प्रकाश संष्लेषण रूक जाता है। इसके फलस्वरूप पौधों की वृद्धि रूक जाती है व उपज में कमी हो जाती है। अत्यधिक प्रकोप होने पर पौधे भी सूख जाते हैं।

नियंत्रण: इसके नियंत्रण के लिये रोगर या डेमाक्रान या मोनोक्रोटोफास किसी भी एक कीटनाशक दवा को 10 से 20 मि. ली. दवा 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जिसके फलस्वरूप यह कीट जमीन पर गिर जाते हैं और फिर दोबारा यह तनो पर चढ़नें लगते हैं। दवा छिडकाव करते समय पौधों के थालो के पास भी छिडकाव 6-7 दिन के अंतर पर करें और आस-पास खरपतवार को उगने न दे।

सीएम की अनुपस्थिति में फैसले लेगा तीन सदस्यीय पैनल

मुंबई (कासं)। महाराष्ट्र सरकार ने तीन मंत्रियों की एक समिति बनाई है जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अनुपस्थिति में कोई आपात स्थिति आने पर फैसले ले सकेगी। इस समिति के सदस्य हैं चंद्रकांत पाटिल (राजस्व मंत्री), सुधीर मुंगंतीवार (वित्त एवं योजना मंत्री) और गिरीश महाजन (जल संसाधन मंत्री)। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 जून को जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि जब भी मुख्यमंत्री आधिकारिक दौरे पर देश से बाहर होंगे तो ऐसी स्थिति में उक्त समिति फैसले ले सकेगी, उसे ये शक्तियां दी गई हैं। इस फैसले के पीछे महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य है कि आनेवाले समय में अगर कभी सीएम बाहर हों तो राज्य में अव्यवस्था ना उत्पन्न हो और प्रशासन और व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे।

डेयरी उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से घरेलू कंपनियों में जगी आस

मुंबई (कासं)। पनीर, मक्खन और स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) जैसे मूल्य संवर्धित उत्पादों के दामों में तेज इजाफे से अगली दो तिमाहियों में डेयरी कंपनियों के सकल राजस्व और शुद्ध राजस्व को सहारा मिलने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े बताते हैं कि उसका डेयरी मूल्य सूचकांक अप्रैल की तुलना में 11 अंक (5.5 प्रतिशत) बढ़कर मई में 215.2 अंक पर रहा। सूचकांक में यह इजाफा मुख्य रूप से न्यूजीलैंड से आपूर्ति में तंगी की वजह से हुआ। यह सूचकांक मूल्य मई 2017 की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक बैठता है, लेकिन फिर भी फरवरी 2014 के शीर्ष स्तर से 22 प्रतिशत कम है। हालांकि, घरेलू बाजार में डेयरी उत्पादों के दाम तकरीबन स्थिर रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनमें तेज इजाफा दिखाई दिया है। इससे स्थानीय भागीदारों के लिए निर्यात के जरिये बेहतर आमदनी की कुछ गुंजाइश बनी है। अमूल ब्रांड से डेयरी उत्पाद बनाने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक आरएस सोढी ने कहा कि कम आपूर्ति की वजह से हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य संवर्धित उत्पादों के दाम उछल चुके हैं। इस कारण, भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से बेहतर आमदनी प्राप्त करने के लिए अपनी खेपों को तेज कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सफेद मक्खन के दाम 250 रुपये प्रति किलोग्राम पर बोले जा रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह दाम 380-390 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पनीर के दाम 6,800 डॉलर प्रति टन बोले गए हैं, जबकि भारत में दाम 400 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम हैं।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जांच-परख कर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचार पत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता।

विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचार पत्र समूह के मुद्रक, सम्पादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं विज्ञापन में उल्लेखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने से पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

- ZINC EDTA/COPPER
- EDTA/FF/EDTA
- 100% WATER SOLUBLE
- FERTILIZER (NPK)
- HUMIC ACID
- SEAWEED EXTRACT
- AMINO ACID
- POTASSIUM HUMATE
- FULVIC ACID
- EDDHA
- NATCA
- BRASSINOLIDE
- DAP
- SODA ASH
- SODIUM SULPHIDE
- AMONIUM CLORIDE
- SODIUM BICARBONATE
- CALCIUM CARBIDE
- PHOSPHORIC ACID
- TRI SODIUM PHOSPHATE
- CITRIC ACID
- STPP

ALL KIND OF INORGANIC

ORGANIC CHEMICALS

CONTACT NO. 022-6710-3722

नई फसल आने से पहले ही चीन ने भारत से कपास के आयात सौदे किए, भाव में रहेगी तेजी

मुंबई (कासं)। चीन ने भारत से कपास की नई फसल के नवंबर-दिसंबर की शिपमेंट के आयात सौदे शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार चीन के करीब 4 से 5 लाख गांठ (एक गांठ-170 किलो) के आयात सौदे किए हैं। घरेलू मंडियों में कपास की नई फसल की आवक सितंबर-अक्टूबर में बनेगी। कॉटन एसोसिएशन आफ इंडिया (सीएआई) के अध्यक्ष अतुल एस. गणात्रा के अनुसार चीन के आयातकों ने कपास की नई फसल के आयात सौदे नवंबर-दिसंबर शिपमेंट के शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार चीन द्वारा कपास के आयात सौदे 86 से 92 सेंट प्रति पाउंड (सीएंडएफ) किए गए हैं। न्यूयार्क कॉटन वायदा में 13 जून को कपास का भाव 94 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ था। उत्तर भारत के राज्यों में कपास की बुवाई समाप्त हो चुकी है जबकि अन्य राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में बुवाई चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ में कपास की बुवाई घटकर 12.48 लाख हैक्टेयर में ही हो पाई है जबकि पिछले साल इस समय तक 14.06 लाख हैक्टेयर में कपास की बुवाई हो चुकी थी। कपास व्यापारी नरेश राठी ने बताया कि चालू सीजन में घरेलू मंडियों में कपास के भाव उंचे रहे हैं, इसलिए प्रमुख उत्पादक राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में कपास की बुवाई ज्यादा होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि चालू सीजन में निर्यात ज्यादा हुआ है जबकि आयात में कमी आई है इसीलिए घरेलू मंडियों में भाव तेज बने हुए है। इस विश्व बाजार में भारतीय कपास सबसे सस्ती है इसलिए निर्यात मांग अच्छी बनी रहने का अनुमान है जिससे घरेलू मंडियों में इसके भाव में और भी तेजी आने का अनुमान है।

सीएम फडणवीस ने किए बड़े प्रशासनिक तबादले

मुंबई (कासं)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई सारे फेरबदल कर प्रशासनिक अधिकारियों को इधर से उधर स्थानांतरण किया हैं। जानकारी के अनुसार, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव को महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। गृह विभाग की जिम्मेदारी सुनील पोरवाल के कंधे पर डाल दिया गया है। उद्योग विभाग के नए अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई होंगे। गवई के पर्यावरण विभाग की जिम्मेदार प्रमुख सचिव अनिल डिग्गीकर संभालेंगे। उच्च और तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है। परिवहन और बंदरगाह विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सौनिक को लोक निर्माण विभाग में लाया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आशीष कुमार सिंह को सौनिक की जगह भेज दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृणा को स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उस विभाग के अधिकारी नंद कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में प्रधान सचिव व प्रोटोकॉल दिया गया। राजगोपाल देवरा को वित्त विभाग में प्रधान सचिव (सुधार) नियुक्त किया गया है। एमएम सूर्यवंशी को नाशिक में जनजातीय विकास निगम और एमएसओ-ओप के प्रबंध निदेशक रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। संजय मीना का ठाणे में अतिरिक्त जनजातीय आयुक्त के रूप में तबादला किया गया है।

चार सालों में नेफेड ने की रिकार्ड दलहन व तिलहन की खरीद

मुंबई (कासं)। किसानों से दलहन, तिलहन और प्याज की उपज की खरीद करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) ने वर्ष 2017-18 में 31.91 लाख मीट्रिक टन दलहन तथा तिलहन की खरीद की है। इससे 20 लाख से भी ज्यादा किसानों को सीधा लाभ मिला है। किसानों के बैंक खातों में पैसे का सीधा हस्तांतरण हुआ है। इससे खरीद की व्यवस्था और सुदृढ़ हुई है। नेफेड के व्यावसायिक आंकड़ों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और संकेत बता रहे हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में भी नेफेड रिकॉर्ड लाभ अर्जित करने की दिशा में अग्रसर है।

नेफेड ने पिछली संप्रग सरकार के चार वर्षों (2011-14) में किसानों से महज आठ लाख मीट्रिक टन दलहन एवं तिलहन की खरीद की थी। राजग सरकार के कुशल नेतृत्व में किसानों से इन चार वर्षों में समर्थन मूल्य पर 64 लाख मीट्रिक टन दलहन व तिलहन की खरीद की गई।

गेहूं की एमएसपी पर खरीद 352 लाख टन के करीब

नई दिल्ली (विसं)। चालू रबी विपणन सीजन 2018-19 में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद 351.95 लाख टन की हो चुकी है जबकि उत्तर प्रदेश की मंडियों में अभी भी गेहूं की आवक बनी हुई है इसलिए खरीद में और भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार चालू रबी में खरीद बढ़कर 351.95 लाख टन की हो गई है जोकि तय लक्ष्य 320 लाख टन से ज्यादा है। पिछले साल समर्थन मूल्य पर केवल 308.25 लाख टन गेहूं की खरीद ही हो पाई थी। प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब से गेहूं की खरीद बढ़कर चालू रबी में 126.90 लाख टन की हो गई है जबकि पिछले साल राज्य से केवल 117.04 लाख टन गेहूं ही खरीदा गया था। हरियाणा से चालू रबी में समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 87.39 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है जबकि पिछले साल राज्य से केवल 74.32 लाख टन गेहूं ही खरीदा गया था। इन राज्यों की मंडियों में आवक बंद होने के कारण खरीद भी बंद हो चुकी है।

उदित ओवरसीज प्रा.लि.

राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक अब मान्यता प्राप्त दरों व अनुदान पर उपलब्ध

फर्टिलाइजर
1. जिंक सल्फेट 21 प्रश.
2. जिंक सल्फेट 33 प्रश.
3. फेरस सल्फेट 19 प्रश.
4. कॉपर सल्फेट 24 प्रश.
5. मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 प्रश.

बायो फर्टिलाइजर
1. राइजोबियम पाउडर
2. एजेटोबेक्टर पाउडर
3. पी.एस.बी. पाउडर

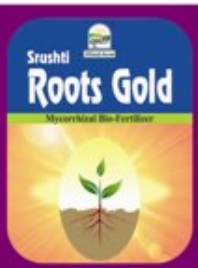

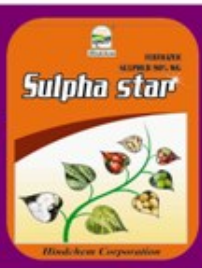

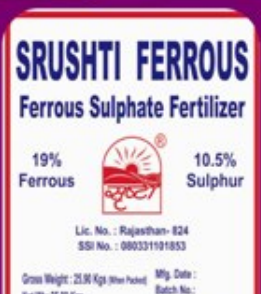

FERTILIZER
- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- FERROUS EDTA 12%
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

BIO FERTILIZERS
- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

WELCOME INQUIRY Contact : 7975653498 (Rajesh

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - सुरेश जी. शर्मा की ओर से सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, शर्मा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-63 से मुद्रित किया और 307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा, Contace Detail : Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com RNI No. MAHHIN/2013/49425